कविता

बनाकर अपनी सरकार

– प्रेम सोनवाले

कितने हिंसक-हत्यारे
राजनीति के अंदर
बन बैठे सरकार
बाहर रह गये
जिनकी थी दरकार।
कुछ बाहुबली
काले धंधे वाले
खुले दिल से
कर रहे हैं भ्रष्टाचार।
कन्याओं और महिलाओं का
शारीरिक-मानसिक
हो रहा है बलात्कार बार-बार
खरीदी-बिक्री का
खुला बाजार
लगता है पौरुष लाचार
खुलेआम हो रहा अत्याचार।
नारी-पुरुष की समानता
शून्य हो गई
पता नहीं किस जंगल में
खो गई
न्याय एक दीर्घ प्रक्रिया
झेल रही कष्ट
ग़रीबों की आबादी
कहां गई आज़ादी
शायद गुलामी कर रही है
चंद लोग़ों की
बाहुबली सत्ताधारियों की।
फिर भी सज़ा पा रहे
कुछ शातिर
अपने अपराधों की
कुछ राजनीति सज्जन-साधु
अब जेल के अंदर
कर रहे भजन
कि शीघ्र निकलकर
फिर करे लंद फंद
धन का अर्जन-अर्चन
बनाकर अपनी सरकार
जनता को लूटने की दरकार

मज़दूर मोर्चा

नियमित रूप से हर माह की पहली व सोलह तारीख को प्राप्त करने के लिए अपने हॉकर से संपर्क करें।

कोई दिक्कत होने पर फ़रीदाबाद के पाठक शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर तथा बल्लभगढ़ के पाठक अरोड़ा न्यूज़ एजेन्सी फोन नं 9811477204।

पेज एक का शेष

सड़क दुर्घटनाओं में उस दिन मुंडे के अलावा 399 और भी मरे थे

मुंडे को तो फिर भी मात्र बीस मिनट में देश की बेहतरीन डाक्टरी सहायता उपलब्ध करा दी गयी, उनकी चिन्ता किसको है जो सड़क पर घंटों पड़े रहकर तड़प-तड़प कर दम तोड़ देते हैं। पुलिस के डर से अव्वल तो कोई किसी दुर्घटनाग्रस्त को हाथ लगाने से गुरेज करता है और यदि किसी ने हिम्मत करके पीड़ित हस्पताल पहुंचा भी दिया तो वहां की लचर व्यवस्था उसको मार डालती है।

मुंडे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ़आ गया कि उनकी मौत तीव्र गति का झटका लगने से लगी अन्दरूनी चोटों की वजह से हुई है। यदि उन्होंने नियमों का पालन करते हुए सीटबैल्ट बांधी होती तो न तो उन्हें झटका लगता और न ही उनकी मौत होती। ईमानदारी से देखा जाये तो यह मामला मंत्री जी द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन का बनता है। यदि उन्होंने लाल बत्ती की उल्लंघना नहीं भी की तो भी सीट बैल्ट न बांध कर तो नियम की उल्लंघना की है। इस पर भी यदि न्यायपालिका का लोकतांत्रिक दबाव न होता तो टैक्सी ड्राईवर पर हत्या का मुकदमा तो अब तक लाद दिया गया होता। हालात को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शासक वर्ग को मुंडे के मरने से ज़्यादा दुख टैक्सी ड्राईवर को जमानत मिलने से हो रहा था।

देश में सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो किसी ने भी कभी इस बात पर गौर करने का प्रयास नहीं किया कि आखिर हर साल इतने लोग सड़क दुर्घटनाओं में क्यों मर जाते हैं। हां जब कभी कोई मुंडे, साहब सिंह वर्मा, राजेश पायलट सरीखा मरता है तब जरूर सरकार इस विषय पर सोचती है, वह भी केवल उसकी तेरहवीं तक, बाद में फ़िर लम्बी तानकर सो जाती है। कभी भी कोई यह जानने का प्रयास नहीं करता कि सड़क निर्माण से लेकर यातायात नियमन में आखिर दोष कहां है?

अरबों-खरबों रूपया सड़क निर्माण पर खर्च हो रहा है, परन्तु उनके निर्माण में क्या मौलिक खामियां हैं? किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया कि पैदल कहां चलेंगे, साइकिल कहां चलेंगी, सड़क पार कैसे कराई जोयेगी, आदि का कोई प्रावधान नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात को नियंत्रित करने वाली ट्रैफ़िक पुलिस का ध्यान केवल उगाही पर रहता है। और कानून से ऊपर रहने वाले लोगों पर तो कोई कानून लागू हो ही नहीं सकता। उन्हें न तो सीटबैल्ट बांधने की जरूरत है न लालबत्ती पर रूकने की। ये तथाकथित वीवीआईपी लोग अवैध रूप से काफिले बनाकर, सायरन बजाते हुए अति तीव्र गति से चलते हुए सड़कों पर पूरा आंतक का माहौल बना देते हैं। हरियाणा के सीएम हुड्डा के ऐसे ही एक काफ़िले ने गत वर्ष करनाल में एक पूर्व आईएएस अधिकारी आर.डी. श्योकंद की जान ले ली थी। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की काफिलेबाज़ी में कोई सुधार नहीं हुआ। वे ज्यों के त्यों सड़कों पर विचर रहे हैं।

सड़क पर सुरक्षा नहीं। क्यों?

सड़क पर सुरक्षा या दुर्घटना में तीन तत्वों की भूमिका रहती है - स्वयं सड़क, सड़क पर चलने वाले वाहन और वाहन को चलाने वाले चालक सड़क दुर्घटना में सबसे अधिक मौतें पैदल और दुपहिया चालकों (70 प्रतिशत) की होती है। इसका कारण स्वयं सड़क है। क्योंकि सड़क की इंजीनियरिंग ऐसी होती है कि उस पर पैदल या दुपहिया वालों के इस्तेमाल के लिए जगह नहीं होती। लिहाजा अपनी राह जाते या सड़क पार करते हुए इनमें से सभी पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है।

चार पहिया हल्के वाहनों में बैठने वालों या इन्हें चलाने वालों की दुर्घटनाये प्राय: अधिक गति या शराब पीकर वाहन चलाने से होती है। सड़क की त्रुटिपूर्ण संरचना भी काफी हद तक इन वाहनों की दुर्घटना का कारण बनती है। भारी वाहन जैसे ट्रक या बस इत्यादि मुख्यत: वाहन में कमी के कारण दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। इनकी तकनीकी जांच पड़ताल नहीं होती और प्राय: इनके मालिक खराब हो रहे पुर्जो को समय पर बदलते भी नहीं। मुनाफे का लालच उन्हें वाहन की स्थिति के प्रति उदासीन रखता है। जिन सरकारी महकमों को इन वाहनों को फिटनेस सर्टीफ़िक्रेट देना होता है वे नियमित रूप से उगाही करते हैं और फर्ज़ी सर्टीफ़िक्रेट जारी करते रहते हैं। उपरोक्त तीनों श्रेणियों की दुर्घटनाओं में ट्रैफ़िक पुलिस का अप्रत्यक्ष योगदान रहता है। वे ट्रफ़िक नियमों को लागू कराने की बजाय 'उगाही' पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी समझते हैं। क्या इन तमाम हालात की जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों को प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए?

मोदी को कद्दावर दिखाने में लपेटे गये बेगुनाह

दो महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और इस छवि की बदौलत ही मोदी स्वयं को जनता के रखवाले के रूप में स्थापित करना चाहते थे। हुआ भी यही और चुनावी फसल मोदी ने जमकर काटी इसके बाद बन्जारा एंड कम्पनी ने गृह राज्यमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मोदी को और बड़ा कद्दावर नेता सिद्ध करने की मुहिम शुरू कर दी। एक के बाद एक झूठी मुठभेड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। हर बार बन्जारा एंड कम्पनी द्वारा गिराये गये व्यक्ति को खूंखार आंतकवादी घोषित कर दिया जाता। यहां तक कि मोदी के प्रतिद्वंदी पूर्व गृह राज्यमंत्री हरेन पांड्या की हत्या को भी 'आंतकवादियों' के मत्थे मढ दिया गया। इस मामले में भी निरपराध व्यक्तियों को फंसाया गया था। जो अदालत से बरी हो गये। असली दोषी तुलसीराम प्रजापति को बाद में झूठी मुठभेड़ दिखाकर मार दिया ताकि राज सदा के लिए दबा रहे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में मोदी का नाम आने के बावजूद मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। कार्पोरेट द्वारा संचालित मीडिया, कार्पोरेट के चहेते मोदी पर सवाल क्यों उठायेगा। डर यह है कि कद्दावर पीएम बनने की धुन से कहीं मोदी उन्हीं पुरानी गलतियों को फिर न दोहराने लगें। यह डर इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को भी एक चरमपंथी पुलिस अधिकारी के रूप में ही जाना जाता है। ये गलतियां समूचे राष्ट्र को महंगी पड़ेगी। देश की जनता ने तो विकास सुशासन और अच्छे दिनों की आशा में मोदी को वोट दिया था। इसलिए नहीं कि देश में आंतकवाद का तांडव शुरू कर दिया जाये और भारत की दशा पाकिस्तान जैसी होकर न रह जाये।

स्कूलों की हालत खराब बच्चे हो रहे बर्बाद

-अनूप चौधरी

फ़रीदाबाद 9 जून। ज़िले की 255 प्राथमिक पाठशालाओं में ज़्यादातर की हालत खराब है। स्कूल के नाम पर दस गुणा बारह फुट का एक अदद कमरा है, वह भी जर्जर हालत में है। शिक्षकों को नियंत्रित करने के लिए हैड टीचर तक भी नहीं। जब पाठशालाओं में यह है सूरते हाल तो कैसे सुधरेगा शिक्षा का स्तर और कैसे होगा नए भारत का निर्माण यानी कुल मिलाकर ज़िले की पाठशालाओं में पढाई व्यवस्था भगवान भरोसे ही है। ओल्ड फ़रीदाबाद स्थित बसेलवा कालोनी में एक ऐसी भी प्राथमिक पाठशाला है, जहां दस गुणा बारह के एक कमरे में कई कक्षाऐं चल रही हैं। वर्तमान हुड्डा सरकार ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कागजी कार्रवाई तो की लेकिन जमीनी स्तर पर शिक्षा में सुधार के प्रयासों में अभी तक भी असर देखने को नहीं मिला है। जिन स्कूलों में पिछले साल शून्य परिणाम रहा, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भी शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। यही कारण है कि आज की तारीख में भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा दिलाने से गुरेज करता है। बताया जाता है कि ज़िले के विभिन्न हिस्सों में 255 के करीब प्राथमिक पाठशालाऐ हैं, जिनमें एक दर्जन से ज़्यादा ऐसी पाठशालाऐं भी हैं, जहां क्लास तो ज़्यादा हैं लेकि न उनके बैठने के लिए कमरे कम हैं। कई पाठशालाएं तो आज भी सदियों पुराने गुरुकुल व्यवस्था की याद को ताजा करा रही है। इन पाठशालाओं में कमरे न होने की स्थिति में छात्र खुले मैदान में पेड़ों के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

बात सिर्फ स्कूल में कमरे न होने तक ही सीमित नहीं है। मई माह में पूरे महीने कक्षाएं लगती है, तब तापमान 40 डिग्री से ऊपर होता है, दिसम्बर और जनवरी माह में तापमान 0 से 10 डिग्री होता है ऐसे में बच्चे खुले में पढने के लिए मजबूर हैं, जबकि शिक्षा विभाग के आला अधिकारी वातानुकूलित कमरों में शिक्षा की नीतियां बनाते हैं।

पिछले चार सालों से फ़रीदाबाद जिले में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में किसी भी हैड टीचर की नियुक्ति नहीं की गई। ज़िले के 255 स्कूलों में से 150 स्कूलों में प्रधान शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 65 स्कूलों में हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने प्रधान पदों की मंजूरी नहीं दी है। ज़िले के 40 स्कूल ऐसे हैं, जहां प्रधान शिक्षक हैं। स्कूलों में प्रधान शिक्षक न होने की स्थिति में शिक्षक भी निरंकुश हो चुके हैं। न तो शिक्षकों के कोई स्कूल आने का समय है और न ही जाने का। जब मन करता है शिक्षक स्कूल से चल देते हैं, जबकि अधिकारियों की मोनीटरिंग नहीं के बराबर है। स्कूलों में बढती अनुशासनहीनता का ही नतीजा है कि प्राथमिक पाठशालाओं में सफलता का ग्राफ़ बढ़ने की बजाय नीचे गिरता जा रहा है। खास बात यह है कि आदर्श कॉलोनी, नेहरू कॉलोनी, संजय कॉलोनी बल्लभगढ़, सब्जी मंडी बल्लभगढ़, इंद्रा नगर, मिल हार्ड कॉलोनी, एकता नगर, सुभाष नगर, राजीव नगर, संत नगर, ध्रुव का डेरा, बाबूलाल का डेरा, महतो डेरा के अलावा अन्य कई जगहों पर स्थित स्कूलों में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कई स्कूल तो ऐसे भी है, जिनमें तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर कार्य किए जा रहे हैं। नियम अनुसार 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए जबकि ज़्यादातर स्कूलों में 40 से लेकर 50 छात्रों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। इसके अलावा शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा गैर शिक्षण कार्यों में भी लगा दिया जाता है।

ज़िला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामपाल सिंह सांगवान का कहना है कि विभाग ने प्रधान शिक्षकों के लिए आवेदन मांगे थे और आवेदन मांगने की अंतिम तिथि 15 मई थी। पंचकूला स्थित विभाग के मुख्यालय द्वारा इस मामले में जल्द कारवाई अमल में लाए जानें की उम्मीद है। उधर डीई ओ राजीव अरोड़ा का कहना है कि रिक्त पदों को भरने का काम मौलिक शिक्षा विभाग का है और वे कई बार इस बारे में विभाग को सूचित कर चुके हैं। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष चतर सिंह का कहना है कि स्कूल में प्रधान शिक्षक के न होने से अनुशासन नहीं रहता है और शिक्षा का स्तर भी गिरता है।